● वर्ष-2
● अंक-231
रायपुर, शुक्रवार
19 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

असली शराब पीने से होने वाली मौतें

प्रदेश में शराब लगातार एक राजनीतिक विषय बना हुआ है, 2018 के पहले डॉ. रमन सरकार में शराब की समस्या पर विधानसभा में चर्चा होती थी। ऐसी रिपोर्ट आती रही जिसमें कहा गया छत्तीसगढ़ शराब पीने में अव्वल राज्य है। दूसरी ओर सरकार ने शराब की पूर्ण बंदी के स्थान पर आंशिक बंदी का रास्ता निकाला और पहले 500 की आबादी और उसके बाद 1000 की आबादी वाले गांवों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई। इसका असर यह हुआ कि कोचिए गांव में जाकर शराब का अवैध कारोबार करने लगे। भारत माता वाहिनी का गठन किया गया, गुलाबी गैंग की महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ हाथ में लाठी लेकर मोर्चा खोला दिया। कुल मिलाकर सरकार की सामाजिक बुराई को देखते हुए हर एक अंकुश लगाने की मांग महिलाओं की ओर से आती रही क्योंकि ये ही इस नशे की सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। महिलाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया। सरकार बनी लेकिन चार साल के बाद शराबबंदी करने में सरकार हिचक रही है। एक तरफ एक समिति का गठन किया गया है जिसकी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई है दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्पष्ट यह कह रहे हैं कि प्रदेश में सरकार शराबबंदी नहीं करेगी। इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि शराबबंदी के बाद नशे के आदी नकली शराब पियेंगे और उनकी मौत होगी। इसका उदाहरण कोरोना काल में लॉकडाउन के समय शराब नहीं मिलने के कारण सिर्फिर या सेनेटाइजर पीने से हुई दो लोगों की मृत्यु को बताया जा रहा है। लेकिन शराब नहीं मिलने से कितने शराब के आदी इस नशे से दूर हो गए थे, इसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं होगी? इससे इतर जो अपराध और दुर्घटनाओं में मौतें असली शराब पीने के कारण हो रही है, क्या सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड है? समाचार पत्र में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब शराब पीने के लिए पैसे के लिए, शराब पीने के बाद नशे में लड़ाई होने के कारण हत्याओं की खबरें नहीं छपती। एक बेटे ने अपने माता-पिता और दादी की हत्या शराब की लेट के चलते कर दी। क्या यह मौतें शराब के कारण नहीं हो रही हैं। सरकार पर 2000 करोड़ रूपए के शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं, ये आरोप राजनीतिक नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छानबीन के बाद कोर्ट में हलफनामा देते हुए हुए लगाए गए हैं। इस बात पर सरकार पीठ थपथपा सकती है कि शराब से जबरदस्ती छोड़ना बड़ा रहा है। लेकिन पर लगातार के पीछे कितने परिवार का दर्द छुपा है, उसका आंकलन कौन करेगा? सरकार को चाहिए कि शराबबंदी न सही, शराब के कारोबार, बिक्री की मात्रा को नियंत्रित तो करे।

कर्नाटक में कांग्रेस को अभी भी है बगावत का डर

सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर ही लिया है। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव तक शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 20 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बावजूद पार्टी के सामने दो बड़ी मुश्किलें हैं। अगर इसका समाधान जल्द नहीं होता है तो कर्नाटक में कांग्रेस को मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। 14 मई को कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए तीन पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि पहली संख्या में विधायकों ने इसी बैठक में सिद्धारमैया को सीएम बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया था। हालांकि, बैठक में एक लाइन में पारदल पास करवा गया कि सीएम पर फैसला मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे। 15 मई को तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट खरगे को दी।

पहली ने उसी दिन डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया। सिद्धारमैया दोपहर तक पहुंच गए, लेकिन डीके शिवकुमार जन्मदिन होने की वजह से दिल्ली नहीं पहुंचे। अगले दिन यानी 16 मई को डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे। इसी दिन खरगे के आवास पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद खरगे और राहुल ने अलग-अलग शिवकुमार और सिद्धारमैया से बात की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी।

17 मई का दिन सबके लिए काफी अहम रहा। इस दिन कई राउंड की बैठकें हुईं। राहुल गांधी ने अपने आवास पर केंद्रीय पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। वहीं, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील शिंदे के साथ मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की।

खरगे ने पहले पर सीनियर गांधी से बात की। बाद में सोनिया ने डीके शिवकुमार को खरगे और राहुल से मिलने के लिए कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल ने सोनिया गांधी से बात भी कराई। इसके बाद डीके शिवकुमार उप-मुख्यमंत्री पद के लिए मान गए। साथ में उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने को भी कहा गया। 18 मई की दोपहर 12.30 बजे कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम, डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने का आधिकारिक एलान कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया को अभी दो साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद कर्नाटक की कमान डीके शिवकुमार को दे दी जाएगी। लेकिन इस बीच पावर क्लैश होना आम होगा। सिद्धारमैया नहीं चाहेंगे कि उनपर डीके शिवकुमार किसी भी तरह से भारी पड़ें और शिवकुमार सिद्धारमैया को खुद से आगे जाने नहीं देना चाहेंगे। ऐसे में इन दो साल के अंदर खुलकर जंग हो सकती है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अगर ये जंग अभी से शुरू हो गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका भारी असर पड़ सकता है। इस तरह के संघर्ष पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में देख चुकी है। इसका उसे नुकसान भी हो चुका है।

हाईकमान को दी चेतावनी, दलित उपमुख्यमंत्री नहीं तो विरोध

बेंगलुरु। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकमान को चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो पार्टी को उसका असर देखने को मिलेगा। शिवकुमार की घोषणा के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर (71) ने कहा कि सबको अपना-अपना नजरिया है। शिवकुमार ने जो घोषणा की, वह उनके हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन आलाकमान का नजरिया अलग होगा। परमेश्वर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो मेरे बिना कुछ बोले दिलेरी शुरू हो जाएगा। पार्टी बात को दलित के मुद्दे को महसूस करे। इससे अच्छा है कि वह पहले ही सतर्क हो जाए और जल्द इस संबंध में निर्णय ले लें। तुमकुरु जिले में जन्मे परमेश्वर कोरटागेरे विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। परमेश्वर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही परमेश्वर ने प्रदेश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की संभाला है। परमेश्वर प्रदेश के इकलौते लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिनका कार्यकाल आठ साल का था।

मंत्रिपद के लिए भी जोर आजमाइश होगी

कांग्रेस में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम के लिए नहीं, बल्कि मंत्रिपद के लिए भी जोर आजमाइश होगी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही गुट के विधायक खुद को मंत्री पद पर देखना चाहेंगे। उधर, दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद कहा कि इससे दलित समुदाय आहत हुआ है। कर्नाटक में दलित सीएम की डिमांड जायदा थी। मैं भी सरकार चला सकता था। अगर सीएम नहीं ही तो कम से कम मुझे डिप्टी सीएम ही बना देते।

भाजपा को इसका फायदा हो सकता है?

इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र से बात की। उन्होंने कहा, अगर समय रहते पार्टी के अंदर का विवाद सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अंदाजा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। समय-समय पर दोनों के बीच विवाद होना लाजिम है। इसका सीधा फायदा भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। दो साल बाद अगर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की लड़ाई बढ़ जाती है तो पार्टी में फूट भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस को नुकसान होगा।

कश्मीर में हो रही अपहरण की खौफनाक साजिश

जितेंद्र भारद्वाज

जम्मू-कश्मीर में होने वाली 9%जी20% की बैठक से पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन, परंपरागत हमलों से पर जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फ्लानिंग कर रहे हैं। चूंकि कश्मीर घाटी के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, इसलिए आतंकियों का प्रयास है कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए, जिसका अंदाजा सुरक्षा बलों को न हो। पुख्ता इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, एनएसजी, मार्कोस व कोबरा कमांडो, घाटी को घेरे हैं। इस सुरक्षा घेरे ने परंपरागत आतंकी हमला, जैसे हैंड ग्रेनेड फेंकना, एंबुश, भीड़ में फायरिंग और आईईडी विस्फोट की संभावना को काफी हद तक कम कर दिया है। अब आतंकी संगठन, 9%जी20% की बैठक से पहले कश्मीर में 9%अपहरण% की खौफनाक साजिश रच रहे हैं। यानी उनके द्वारा किसी बस या हाउस बोट का अपहरण किया जा सकता है। इसके मद्देनजर मार्कोस कमांडो को डल झील में उतारा गया है।

सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों की इस अचूक तैयारी के चलते आतंकी, हैंड ग्रेनेड फेंकने, आईईडी लगाए या फायरिंग करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। इसी वजह से वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई नया तरीका खोज कर रहे हैं। इसके तहत आतंकियों द्वारा अपहरण की किसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। सवारियों से भरी किसी बस को अपने कब्जे में ले लेना, हाउस बोट का अपहरण और दूर दराज की किसी जगह पर कुछ घरों को बंधक बना लेना, आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा है।

विदेशी मेहमानों का सड़क रूट सैनिटाइज

सुरक्षा बलों से मिले इनपुट के मुताबिक, आतंकी संगठनों को हमले का कोई मौका नहीं मिल रहा है। घाटी में पहाड़, जंगल, झील, सड़क मार्ग, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, बाजार और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर आर्मी, जेएंडके पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कोबरा, मार्कोस, एनएसजी, एसएसबी और बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया है। जिन जगहों पर भीड़ की ज्यादा आशंका होती है, वहां पर कोबरा, मार्कोस और एनएसजी कमांडो तैनात हैं। इसके अलावा जी20 की बैठक में आने वाले विदेशी मेहमानों का रूट सड़क सैनिटाइज कर दिया गया है। विदेशी मेहमान, जिन स्थलों पर बैठक करेंगे या वहां का दौरा करेंगे, वहां भी कमांडो को लगाया गया है। डल झील के आसपास के इलाके में ये कमांडो नियमित गश्त कर रहे हैं। झील में पहले से कोई सिफोटोल के हिप्पाग्रन गया हो, उसके लिए ये कमांडो पानी में उतर रहे हैं।

सीएम की पहल पर गोटूल रच्चा समिति के विदेश भ्रमण का मिला अवसर

रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के कांकेर जिले के आदिवासी बहुल अंतागढ़ के गोटूल रच्चा समिति को इंडोनेशिया के भ्रमण का महत्वपूर्ण अवसर मिला। अध्ययन भ्रमण पर गए समिति के सदस्यों का यह सफर इतना रोचक और अनुभव भरा था कि वे वापस लौटते ही मुख्यमंत्री से विधायक श्री अनूप नाग के नेतृत्व में सीधे मुलाकात करने पहुंचे और अपने अनुभवों को सहजता के साथ साझा किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान सदस्यों ने उन्हें यह खुशी-खुशी बताया कि प्रदेश से बाहर की यात्रा हमारे लिए एक सपना और असंभव सा था, ऐसे में आपने हम आदिवासियों को विदेश की धरती पर छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति, कृषि, परंपरा के प्रदर्शन और उन देशों की कृषि तथा वनोपज में हो रहे नवाचारों को सिखने-समझने का जो महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया, यह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो गया है।

प्रमुख समाचार

सर्वोच्च न्यायालय ने प. बंगाल में द केरल स्टोरी से बैन हटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म के निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 3 मई के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही तमिलनाडु सरकार से फिल्म देखने वालों को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में खुद को इस स्थान पर पाएंगी। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सीजेआई व पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगी।

अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के रूप में संभाला कार्रभार

नईदिल्ली। किरेन रिजिजू की गुरुवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मेघवाल, वर्तमान में संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री, महत्वपूर्ण कानून और न्याय मंत्रालय संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर अर्जुन राम मेघवाल को शुभकामनाएं दीं। वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने एमओएस लॉ एंड जस्टिस के रूप में स्वतंत्र प्रभार संभाल लिया। केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बात करने हुए अपने विजन को सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। न्यायपालिका और सरकार के बीच दूरियों के सवाल पर नए कानून मंत्री ने कहा कि कोई ऐसी दूरियां नहीं हैं।

सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में होगा विपक्ष का शक्ति परीक्षण

बेंगलूरू। कर्नाटक में सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री होंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश करने की भी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं को बुलाया भेजा गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निमंत्रण दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व सीएम महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेकां प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को भी आमंत्रित किया गया है।

गीताप्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन का होंगे हिस्सा

गोरखपुर। धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। गीताप्रेस प्रबंधन के अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने समारोह में आने की स्वीकृति दे दी है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पीएम मोदी के आगमन की तिथि फाइनल नहीं की गई है। गीताप्रेस प्रबंधन ने शताब्दी वर्ष समापन समारोह के लिए 30 मई की तिथि पर समय देने का निवेदन किया है। पीएम के आगमन पर गीताप्रेस की तरफ से श्री शिव महापुराण के विशिष्ट अंक के विमोचन की भी तैयारी की जा रही है।

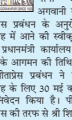

मुंबई 26/11 का आतंकी हमला: पीड़ितों ने आरोपी तहव्वुर राणा के लिए सख्त सजा की मांग की

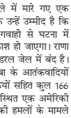

मुंबई। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों में घायल हुई दो महिलाओं ने आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को दी गई मंजूरी का स्वागत किया और कहा कि उसे मौत की सजा या कठोर सजा दी जानी चाहिए। 2008 के आतंकी हमले में मारे गए एक पुलिसकर्मी के पिता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राणा के प्रत्यर्पण और उसकी गवाही से पता चलेगा कि पाकिस्तान की भूमिका का पर्दाफाश हो जाएगा। राणा फिलहाल लॉस एंजेलिस की फेडरल जेल में बंद है। नवंबर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के हमलों के दौरान छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। कैलिफोर्निया स्थित एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी

न्यायपालिका से तल्खी के कारण हट रिजिजू, मेघवाल से सधेगा राजस्थान

अभिनव आकाश

मोदी सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। किरेन रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभालेंगे। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच विभागों का पुनर्आवंटन किया है। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।

जुलाई 2021 में ठीक इसी तरह से रविशंकर प्रसाद का भी कानून मंत्रालय बदल दिया गया था और फिर किरेन रिजिजू का नाम सामने आया। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। इसके पीछे की बड़ी वजह यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार देखने को मिल रहा था। रिजिजू जब से कानून मंत्री बने उन्होंने कॉलेजियम से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ सख्त टिप्पणियां की। पीएम मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण या बयान सामने नहीं आया तो रिजिजू को लगा कि इस पर मोदी सरकार की भी मौन सहमति है। लेकिन सरकार का एक बड़ा मकसद ये होता है कि ज्यूडिशरी से टकराव नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना होता है। बीते दिनों अमित शाह ने भी कहा था कि ज्यूडिशरी और कार्यपालिका के कामों में ओपलैपिंग हो रही है।

बढ़ती गई न्यायपालिका-कानून मंत्री के बीच तल्खी

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को लेकर पिछले साल से केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। जनवरी 2023 में रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा, जिसमें न्यायाधीशों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए निर्णय-अंकन प्रक्रिया में एक सरकारी नामित को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। उसी महीने में रिजिजू ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर केंद्र की आपत्तियों पर गुप्त सर्वेदस्तीफिल रिपोर्ट सार्वजनिक करना एक गंभीर चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट के कदम पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि राँ या आधी की गुप्त या सवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखना गंभीर चिंता का विषय है।मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए रिजिजू ने भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने और इसे सरकार के खिलाफ करने का एक कलिब्रेटेड प्रयास बताया था। कॉन्क्लेव में रिजिजू ने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे और न्यायपालिका को एक विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि देश के खिलाफ काम करने वालों को कोमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक कार्यक्रम आयोजित हुई थी। लेकिन किसी तरह पूरी संगोष्ठी बन गई कि केंद्रीय कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है। रिजिजू ने कहा। था कि कुछ न्यायाधीश ऐसे जो कार्यकर्ता हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो विपक्षी दलों की तरह न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

फैसले की इनसाइड स्टोरी

न्यायपालिका-सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद नजर आया। कॉलेजियम पर किरेन रिजिजू का बयान सामने आया, उससे भी टकराव बढ़ा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और कड़ी टिप्पणियां भी आईं।

राजस्थान विधानसभा चुनाव पर इस वक्त पार्टी का खास जोर है। राजस्थान बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं मेघवाल। मेघवाल को बड़ा मेघवाल देकर ज्यादबल-एससी वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। ये चुनावी वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ही तल्ख टिप्पणियां आती रहीं तो इससे सरकार की इमेज खराब हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने किया धमतरी विधानसभा क्षेत्रवासियों को निराश : भाजपा

■ भेंट मुलाकात मे नहीं मिली कोई बड़ी सौगात

■ जगह जगह हुई भाजपाइयों और पुलिस के बीच नोंक झोंक

धमतरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी विधानसभा के प्रवास पर पहुंचे। उनके इस कार्यक्रम से क्षेत्रवासियों मे खासी उम्मीदें थी। विगत 4 वर्षों से बुरी तरह उपेक्षित धमतरी की जनता को इस सरकार से यह आखिरी उम्मीद थी। धमतरी के लोग इस आस में बैठे थे कि अब शायद धमतरी को मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज मिल जायेगा। पूह पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एग्री मार्ट जैसी सुविधाएं मिल जायेगी। ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, सर्वसुविधा युक्त खेल स्टेडियम, मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा। पर्यटन के विकास को लेकर कोई नई घोषणा होने की उम्मीद थी। स्व सहायता समूह की महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके समूह को नया काम मिलेगा, उनके कर्ज माफहोंगे। किसानों को उम्मीद थी कि मौसम मे बरबाद फसल की क्षतिपूर्ति के लिए कोई बड़ी घोषणा की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़कों का बुरा हाल है उसे लेकर कोई घोषणा नही की गयी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को निराश किया है। अब लोगों की इस सरकार से कोई उम्मीद बाकी नही रही।

भाजपाइयों ने क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात का भरसक प्रयास किया पूरे व्यवस्था मे लगे प्रशासनिक अमले ने भाजपाइयों के साथ अपरापियों की तरह व्यवहार किया। अछोटा से लेकर लोहरसी तक हर जगह भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास परंतु उन्हे मिलने नही दिया गया। पुलिस ने भाजपाईयो के जिलाध्यक्ष हेमंतराज सोनकर, गोविंद खिल्लें सहित पूरा साथियों सहित सुबह से ही उठा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष गाँव के रास्ते भटगाँव जाने के लिए निकले उन्हे खेत मे ही पुलिस द्वारा घेर कर रोका गया। आपधापी मे जिलाध्यक्ष शशि पचार घायल हो गये। घायल अवस्था मे ही उन्हे कोतवाली थाने मे बिठाकर रखा गया। शाम को मुख्यमंत्री के प्रस्थान के बाद जब उन्हे छोड़ा गया तो अस्पताल जाने पर डॉ ने बताया कि उनके टखने की हड्डी टूट गयी है और उन्हे 2 हफ्ते पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह दिया। जिला महामंत्री कविंद्र जैन, अरविंदर भाई, खिलेश्वरी रिकन, रुपया नरेश साहू, बौधीका विश्वास, रीतिका यादव 20 से अधिक महिला एवं युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के हेलिकॉप्टर गुजरते वक्त काला झंडा दिखाया गया और पुलिस अधीक्षक की गाड़ी रोककर उनसे मुख्यमंत्री से मिलने जाने देने की मांग की गयी। उन्हे बेंद्रा नवागांव के पास गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। वरिष्ठ नेता महेंद्र पंडित, सूरज शर्मा साथियों सहित भटगाँव के पास गिरफ्तार किये गये। प्रदेश मंत्री राम गोहरा, हेमलता शर्मा, मोनिका देवांगन सहित महिला मोर्चा की बहनों के साथ प्राम भोयना मे गिरफ्तार हुए। भटगाँव के कार्यकर्ता टिक्की देवांगन सहित अन्य लोगों को सुबह से ही घर से उठा लिया गया । युवा मोर्चा के भेष साहू, तिलक देवांगन, देवेश साहू, बसंत मीनपाल ने लोहरसी रेस्ट हाउस पहुँच कर मुख्यमंत्री के काफिले के सामने नारेबाजी करते हुए काला झंडा दिखाये उन्हे भी उठाकर कोतवाली थाना लाया गया। इसके अलावा विजय साहू, हेमंत चंद्राकर, रोहिताश मिश्रा, कोमल यदु, जितेंद्र पटेल, कौतंन मीनपाल, अविनाश दुबे, लता सोनी, गीता शर्मा, पवन गजपाल सहित 100 से अधिक भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत मे लिया। दिन भर भाजपाइयों को पुलिस ने परेशान किया अनेक स्थानों पर पुलिस और भाजपाइयों मे नोंक झोंक हुई।

बेरोजगारी भत्ते पर हंगामा, भाजयुमो कार्यकर्ताओं का जिला रोजगार कार्यालय पर प्रदर्शन

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपे में गुरुवार को बेरोजगारी भत्ते की लेकर भाजयुमो और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। जिला रोजगार कार्यालय का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। वहां तालाबंदी करने की कोशिश में पुलिस ने उनकी जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं को साढ़े चार साल के हिसाब से 1.35 लाख भत्ता देने की मांग की और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा इन दिनों अलग-अलग जगह प्रदर्शन कर रहा है। इसी के तहत गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत प्रदेश और उपाध्यक्ष जितेंद्र देवांगन के नेतृत्व में एकत्र हो गए। इसके बाद जिला रोजगार कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान पुलिस ने करीब 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ता आगे बढ़ने की प्रयास करने लगे। इसे लेकर पुलिस ने उनकी झड़प हो गई।

इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और जिला रोजगार कार्यालय की ओर दौड़ लगा दी। वहां प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी का प्रयास करने लगे। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते रहे। इस बीच पुलिस के साथ फिर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस के कई जवान और कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 300 पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया गया था।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को गंगा जल हाथ में लेकर रोजगार देने का वादा किया था। बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया। अब जो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दिया जा रहा है, उसे सरकार बनने के बाद से देना चाहिए। अब युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है।

औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर गौठानों का विरोध कर रहे भाजपा नेता: राजेन्द्र साहू

■ अगर क्षेत्रवाद हुआ है तो सबूत दें

अंडा। मनगढ़ंत आरोप लगाना छोटें भाजपा के गौठान चोली अभियान को लेकर जिला सहकारी केन्दीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुद्दाविहीन भाजपा नेता गौठान को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश में हजारों गांवों में गौठान बनाए गए हैं, जिसमें राशि खर्च हुई है। भाजपा नेता इसमें भी घोटाले का आरोप लगा हैं। कहां घोटाला हुआ और कैसे घोटाला कि हुआ, इसका कोई सबूत भाजपा नेताओं के गौठानों पास नहीं है। केवल मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र ने कहा कि गौठानों में गोबर खरीदी हुई, जिससे लाखों गौपालकों की आमदनी बढ़ी। महिला समूह की महिलाओं को रोजगार मिला। गौठानों में गोबर से महिला समूहों ने वर्मी कम्पोस्ट, जैविक खाद, गोकाष्ठ, गोबर के दीये, गमले जैसे उत्पाद बनाकर बेचे जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है। गौठानों के माध्यम से हुए इन सभी कार्यों से कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को सहारा मिला और लोग बेहतर तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं।अब रीपा माध्यम से तेलघानी, पेंट बनाने की मशीन सहित अन्य लघु उद्योग भी प्रारंभ किये जा रहे हैं, जिससे दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गोबर

खरीदी और इससे बनने वाले उत्पादों से किसानों, गौपालकों और मजदूरों के साथ आम जनता को आर्थिक फायदा मिल रहा है। जनकल्याण के लिए बनाई गई इस सशक्त योजना में अगर भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है भाजपा नेताओं को अपने इस दृष्टिदोष का इलाज जरूर कराना चाहिए।

राजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेता शुरू से गोबर खरीदी योजना और गोबर खाद बनाने की योजना का विरोध कर रहे हैं। गोबर खरीदी का विरोध करने वाले भाजपा नेता गौठानों का विरोध कर क्या महिला समूहों और गोबर बेचने वाले गौपालकों के अलावा रीपा में रोजगार पाने वाले का रोजगार छीनना चाहते हैं। रासायनिक खाद बनाने वाले औद्योगिक घरानों की फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

पतंजलि शिविर में 37 मरीज हुए लाभान्वित

कोरबा। 17 मई विश्व उच्चरक्तचाप दिवस पर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका कोरबा में आयोजित विशेष आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में 37 मरीज लाभान्वित हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉ. नागेंद्र नारायण शर्मा ने अपनी चिकित्सकीय सेवायें शिविर में दी। उच्चरक्तचाप व मधुमेह की नियुल्क जांच कर ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह के नियंत्रण एवं उपचार हेतु परीक्षित औषधि भी नियुल्क प्रदान की गई। इस दौरान उच्च रक्तचाप, हृदय एवं हेट स्ट्रोक के लिये उपयोगी श्रशित सुधा शरबत भी नियुल्क पिलाया गया। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवायें प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉ.नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया की आरामदायक और परिश्रम विहीन जीवनशैली, जंकफूड व पित्तवर्धक आहार के आदि हो रहे लोगों में उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की बीमारी बढ़ती जा रही है। उम्र भी बच्चे और युवा वर्ग में भी इस तरह के लाइफस्टाइल जनित रोगों का बढ़ना चिंता का विषय है। इससे बचाव हेतु जंकफूड एवं अनियमित दिनचर्या से परहेज करना आति आवश्यक है, तभी बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी इन गंभीर रोगों से बच सकती है। डॉ. नागेंद्र शर्मा ने बताया कि शर्मा लोग अपनी जीवनशैली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर इन रोगों से आसानी से बच सकते हैं। उक्त शिविर में चिकित्सक डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा,डॉ.संजय वैष्णव के अलावा शिव औषधालय की संचालिका प्रतिभा शर्मा, संजय कुर्मवेशी, नेत्रनन्दन साहू, अश्वनी कुमार, करिव रंजन दास, स्वपन गिरी, कमल धारिया, दामोदर साहू, सिद्धराम शाहनी, राकेश इस्पत एवं चक्रपाणि पांडेय ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भाजपा-कांग्रेस के पदाधिकारी फर्जी दस्तावेज से बेच दी सरकारी जमीन

■ मंत्री के पूर्व सचिव, पटवारी सहित 21 पर एफआईआर

अबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फर्जी दस्तावेज से सरकारी जमीन बेचने के मामले में 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दो अलग-अलग अपराधिक प्रकरणों में क्षेत्र के पटवारी और तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो, भाजपा व कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी-कार्यकर्ता और प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का पूर्व निजी सचिव भी शामिल है। आरोप है कि, बतौली ब्लाक अंतर्गत ग्राम भटगांव, कालीपुर और कदना में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय जमीन का पट्टा बनवाया गया। प्रशासनिक जांच के बाद बतौली थाने में मामला दर्ज किया गया है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी शिकायत

जानकारी के मुताबिक, बतौली से लगे ग्राम पंचायत भटको के ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि शासकीय जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिया गया है। क्षेत्र-विक्रेता के संबंध में गांव वालों की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। शिकायत पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। राजस्व विभाग के टीम की जांच में बतौली ब्लाक के कई गांवों में जमीन घोटाला उजागर हुआ। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर तहसील न्यायालय बतौली में राजस्व प्रकरण की सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान नहीं प्रस्तुत कर सके अभिलेख

सुनवाई में जमीन से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अवसर भी दिए गए। किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित खसरा नंबर की जमीन नियमों के तहत उनके नाम पर आई है। मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बतौली थाने में राजस्व अमले ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर में चार और 19 लोगों को नामजद किया है। इसमें पटवारी व कानूनगो दोनों एफआईआर में नामजद हैं। इन सभी के विरुद्ध धारा 120 बी, 420 , 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।

इन लोगों के विरुद्ध हुई एफआईआर

जमीन घोटाले के एक प्रकरण में पुलिस ने पटवारी कंचन राम पैकरा, तहसील कार्यालय के कानूनगो जान बड़ा, रामनाद यादव, भगवनिया, शशांक गुप्ता, जगमोहन, हेमंत यादव, प्रेमलता, अश्वनी सिंह, भूपेंद्र यादव, अनूप गुप्ता , उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद, प्रदीप गुप्ता, अनीता यादव, बीना गुप्ता और दूसरे प्रकरण में बैगिन लोहार, अमित गुप्ता, पटवारी कंचन राम पैकरा व कानूनगो जान बड़ा के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

वार्ड क्रमांक 14 में महापौर ने किया ध्वज का शुभारंभ

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 14 में ध्वाज का शुभारंभ किया। इस भीषण गर्मी से राहतोंरें व आने जाने पथिकों को ठंडा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हुए पौता काटकर ध्वाज का शुभारंभ किया। उक्त अवसर पर उन्होने बताया कि इस वर्ष गर्मी का मौसम देर से प्रारंभ होने के कारण नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत कुल 40 ध्वाज पर खोलने की कार्यवाही की जा रही हैं ताकि अपने कार्य से घरों से निकले हुए मुसाफिर एवं पंथिकों को शीतल जल प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में वार्ड क्र. 14 में जीतल जल के साथ मीठा का प्रबंध किया गया। माननीय महोदय द्वारा आमजनों से अपील की गई कि वे जब भी इस पथ से गुजरे तो रुककर शीतल जल व मीठा का आनंद लेते हुए थोडी देर विश्राम करते हुए आगे बढ़े। कार्यक्रम में मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर, एल्डरमेन रामगोपाल यादव, मोनू श्रीवास, कौंसल प्रसाद शुक्ला, कौशिल्या बाई, किरण साहू, जितेन्द्र डडसेना, रोशन ठाकुर, ओमप्रकाश, अजय कोसले, रमेश साहू, श्रीनिवास आदि उपस्थित थे।

कोयला खदान में चलाया गया मॉक ड्रिल अभियान

कोरबा। कोरबा जिला के गेवरा दीपका खदान में एनडीआरएफसीआईएफएफ एवं पावर विग्रेड की संयुक्त टीम ने बुधवार को गेवरा दीपका कोयला खदान क्षेत्र मे कोयला खनन के दौरान घटने वाली घटनाओं से अवगत कराने एवं उससे बचाव के लिए की जाने उपायों को बताने को लेकर मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल की शुरुआत खदान क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज व फायरिंग कर खदान क्षेत्र से खदेड़ा गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा वाहनों में आग लगा दिया गया जिसकी तकाहत सूचना पावर विग्रेड को दिया गया आग लगे वाहनों पर नियंत्रण पाने हेतु पावर विग्रेड के कर्मचारियों ने रुपे करते हुए स्थिति पर काबू पाया गया, वाहन में हुए धमाका से खदान एरिया में लैंडस्लाइड होने पर मौके पर कार्य कर रहे हैं मजदूर मलबे में दब गए, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल सुरक्षित जगह में ले जाकर घायलों को तकाल प्रथम उपचार दिया गया और एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

रायफल के साथ 4 शिकारी वन विभाग ने गिरफ्तार किए

महासमुंद। जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के पिलवा पाली गाँव के भैसामुडा बांध के कक्ष क्रमांक 231 में जंगली सूअर शिकार के मामले में 4 जंगली जानवरों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। वन प्राणियों के अवैध शिकार के आरोप में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देर रात तक चली इस छापेमार कार्रवाई में चार आरोपियों को रेंज हौरा गिरफ्तार करने मे सफलता मिली है। बता दें कि पूरा मामला यह है कि महासमुंद जिला के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पीलवा पाली के जंगलों में जंगली जानवरों के शिकार के लिए पांच लोगों ने राइफल हाथ में लेकर वन सिफार पर निकले थे। वहां उन आरोपियों ने जंगली सूअर को बंदूक से शिकार कर घर ले आए। वहां उन लोगों ने जंगली सूअर का मांस पका कर खा गए। कच्चा मांस और 315 बोर के राइफल और पांच जिंदा कारतूस के साथ 2 हंसिया, 1 चाकू और 2 कुल्हाड़ी बरामद की गई है। इस पूरे मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा , 9 39 ,50 ,51 , 52 के तहत अपराध पंजीबध्द कर कार्रवाई की जा रही है।

सीमा कौशिक बनी योग संघ कबीरधाम की जिला सहसचिव

कवर्धा। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए सुश्री सीमा कौशिक जी को उनके योग के प्रति समर्पण व निष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए जिला सह-सचिव कबीरधाम नियुक्त किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अनिल चन्द्राकर ने नवनियुक्त जिला सह-सचिव को बधाई देते हुए कहा कि सुश्री सीमा कौशिक जी कबीरधाम जिला में पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्रदेश महासचिव श्री खोमेश साहू ने उक्त जिला सह-सचिव को डिक्लेटर मनोनयन पत्र प्रेषित कर बधाई के साथ-साथ जिला सह-सचिव के कार्यों, उद्देश्यों व नियमों से परिचित कराकर जिले में समर्पण भाव के साथ कार्य करने का शुभाशीष दिया है। सम्भागाध्यक्ष श्री शैलेंद्र वासनिक ने इसे कबीरधाम जिला में योग के प्रसार में एक अहम कड़ी के रूप में माना है। कबीरधाम जिला अध्यक्ष श्री रोहित चंद्रवंशी जी ने इसे मील का पत्थर बताया हैं। बिंदु सिंह जी ने इसे बिलासपुर परिक्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है।

मनेंद्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत बनेंगे हमर अस्पताल: विधायक

मनेंद्रगढ़। पोडब्यूटी रेस्ट हाउस मनेंद्रगढ़ मे विधायक डॉ विनय जायसवाल ने एक बैठक ली, बैठक मे पूरे मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र मे स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु ढ़ंग से चलाने हेतु चर्चा की गई। साथ ही विशेष तौर से हमर अस्पताल के निर्माण के विषय में चर्चा हुई। मनेंद्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत 7 हमर अस्पताल का निर्माण होना है, जिसमें मनेंद्रगढ़ में 2, झगरा खांड 1, , साजा पहाड़ 1, कोरिया 1, गोदरीपारा 1, छोटा बाजार 1 शामिल हैं। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य विभाग की योजना अंतर्गत पूरे प्रदेश में हमर अस्पताल का निर्माण होगा,जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं मे बढ़ोतरी होगी। शीघ्र ही हमर अस्पताल की निर्माण होगा और जहां निर्माण हो चुके हैं वहां शीघ्र ही हमर अस्पताल आरम्भ होगा। बैठक में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नया उपाध्यक्ष, नगर पंचायत झगरा खांड अध्यक्ष, पार्षद अनिल प्रजापति आदि उपस्थित थे।

केशकाल के चार पार्षदों ने अपने निष्कासन को गलत बताया

■ आलाकमान से मिलकर रखेंगे अपनी बात

केशकाल। विगत दिनों नगर पंचायत केशकाल के वरिष्ठ पार्षद सगीर खान, पार्षद पंकज नान सिन्हा, पार्षद श्रीमती शबनम बानो व पार्षद श्रीमती देवश्री वेटप्पाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेशानुसार प्रभारी महामंत्री (प्रशासन) रवि पांडेय ने एक पत्र जारी कर निष्कासन कर दिया। निष्कासित पार्षदों ने इस गलत ठहराया हैं,उनका कहना है कि निष्कासन के संदर्भ में पार्टी संगठन के नियमों का ही पालन नहीं किया गया इसलिए वे अपनी बात आलाकमान के समक्ष रखेंगे।

मीडया को जानकारी देते ही चारो निष्कासित पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अपना एक संविधान है, जिसमें अनुशासनात्मक नियम 1 के अनुसार अधिकारी जो धारा 16(ख) (4) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा उसे सर्वप्रथम अनुशासनात्मक नियम 5 के अनुसार आरोप की लिखित शिकायत को पहले प्रदेश अनुशासन समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु रखा जाएगा. तदुपरांत अनुशासन समिति द्वारा स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा. ऐसा किए बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु कांग्रेस पार्टी के संविधान को अनदेखी करते हुए ऐसी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की. जबकि कांग्रेस पार्टी के संविधान में निहित अनुशासनात्मक नियम 4 के अनुसार यदि कोई जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के संविधान में निहित नियमों की अवहेलना करेगा तो उसे भी अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी समय मांगते हुए हम अपनी बात रखेंगे और उन्हे उम्मीद है कि पार्टी उन लोगों के साथ न्याय करेगी।

अपने साथ हुए इस असंवैधानिक कृत्य को लेकर वरिष्ठ पार्षद सगीर खान व अन्य पार्षदों ने पार्टी के भीतर रहते हुए आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि इस सारे प्रकरण में निष्कासित पार्षदों को वरिष्ठ पत्रकार एवं लिबरल पार्टी अनि इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहसिन सिद्दाक साहिल का भी पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा न्यायालय का सहारा लेकर जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का घिनौना खेल खेला, इसके विरुद्ध उन्होंने भाजपा सरकार के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा और उसके पदचंद्र की पुरजोर विरोध किया।

महात्मा गांधी नरेगा से जुड़कर वनाधिकार पत्रकधारी का परिवार हो रहा है आत्मनिर्भर

कोरिया। वनांचल में रहने वाले आदिवासी परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने में महात्मा गांधी नरेगा एक कारगर योजना साबित हो रही है। एक ओर वनवासियों को पात्र करार वनाधिकार पत्रक देकर उन्हें काबिज भूमि का अधिकार प्रदान कर रही है वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वनवासियों को वन भूमि को खेती के लायक बनाकर कूंए डबरी से सिंचाई जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के ग्राम पंचायत महाई में रहने वाले वनवासी गुलाब सिंह का परिवार अब वनों में रहकर भी खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रहा है। अपने परिवार के बारे में जानकारी देते हुए आदिवासी वर्ग के

किसान गुलाब सिंह ने बताया कि पहले उनके पास भूमि का अधिकार नहीं था तो उनका परिवार मनरेगा के तहत परिवार श्रमिक बनकर कंचन अकुशल रोजगारमूलक कार्यों में मजदूरी पर ही आश्रित रहता था। उनके पिता महाई के वनों के पास वर्षों से निवासरत थे जिनका उन्हें तीन साल पहले वनाधिकार पत्रक प्राप्त हुआ है। इस परिवार के पास लगभग एक एकड़ वन भूमि है। यहां वह अपनी पत्नी श्रीमती पुखबसिया, बेटी मीराबाई व पुत्र विजय सिंह के साथ निवासरत हैं। वन भूमि का अधिकार पत्र मिलने के बाद गुलाब सिंह के पास एक समस्या थी कि उबड़ खाबड़ इस वनभूमि को बारहमासी खेती के लायक कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्हें याद्दाश्त गांधी नरेगा योजनर्तगत भूमि सुधार का लाभ मिला और वनभूमि को उन्होने मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर खेती के लायक बना डाला। जब खेत बनकर तैयार हुए तो उसमें सिंचाई के साधन के तौर पर मनरेगा योजना अंतर्गत कूप निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत महाई की ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर गुलाब सिंह को निजी वन भूमि पर सिंचाई सुविधा के लिए निजी कूप वर्ष 2019-20 में कुआँ निर्माण की के लिए एक लाख अस्सी हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

हम आतंक के राज का सामना कर रहे हैं-इमरान

इस्लामाबाद। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अपनी पार्टी के कई नेताओं और सदस्यों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी आतंक के शासन का सामना कर रही है। डॉयचे वेले के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक अभूतपूर्व कार्रवाई हो रही है। मेरा एक वरिष्ठ नेतृत्व जेल में है। उन्हें अदालत से जमानत मिल जाती है [और] जैसे ही वे अदालत से बाहर आते हैं, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है अभी, यह आतंक का शासन है जिसका हम सामना कर रहे हैं। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने दोहराया है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। पंजाब सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि उनके लाहौर स्थित घर में करीब 40 आतंकवादी छिपे हुए हैं, खान ने कहा कि सरकार को तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद दोष तरीके से घर की तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि आतंकवादियों की जीवनशैली में उनकी खूब की जान भी खतरे में हो सकती है। पीटीआई नेता बाबर अवान ने कहा है कि युवा नेतृत्व उन सदस्यों की जगह लेगा जो पार्टी छोड़ चुके हैं।

जी20 समिट को लेकर कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

नई दिल्ली। 22 से 25 मई तक कश्मीर में होने वाली बहुप्रतीक्षित जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सब के बीच एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक को लेकर कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बन्दोबस्त किए गए हैं। अपने बयान में एडीजीपी ने बताया कि हमने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं। जिसतरीय सुरक्षा होगी। हवा के लिए ड्रोन रोधी उपकरण लगाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एनएसजी और सेना की मदद ले रहे हैं। जहां तिकाय के लिए – ड्रम क्षेत्र – हम मार्शल और प्रतिनियुक्ति करेंगे, पुलिस तीन भी होगी। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम बैठक को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक संचालित करेंगे।

चीफ सेक्रेटरी को बदलने की तैयारी में केजरीवाल सरकार

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी पीके गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सहमति के लिए एलजी वीके सक्सेना को पीके गुप्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार को 2022 में उनके पद पर नियुक्त किया गया था और वह इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पीके गुप्ता के पास दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार के साथ अक्सर तल्खी भरे रिश्ते रहे हैं। सरकार कई बैठकों पर मुख्य सचिव पर लोगों के काम रोकने का आरोप भी लगा चुकी है। इससे पहले राज्य सरकार ने आशीष मोरे को सेवा सचिव के पद से भी हटा दिया है और नौकरशाह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सीबीआई के बाद अब ईडी के सामने पेश हुईं राबड़ी देवी

पटना। राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की थी। अब ईडी मनी लांड्रिंग के आरोपों के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। नौकरी के बदले जमीन का मामला यादव के परिवार की 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से जुड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मार्च में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से नौकरियों के लिए जमीन मामले में पूछताछ की थी। सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 16 आरोपी लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के अनुसार, लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ प्राथमिक जांच के परिणाम के बाद मामला दर्ज किया गया था।

जातीय जनगणना पर सुको से बिहार सरकार को झटका

पटना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया जारी थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। यह बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बिहार सरकार लगातार राज्य में जातीय जनगणना को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। मामला 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले के न्यायाधीश संजय करोल ने बिहार सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें राज्य में उसके (बिहार सरकार) द्वारा की जा रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सिद्धारमैया के सिर सजेगा कर्नाटक का ताज

कांग्रेस ने की घोषणा- डीके शिवकुमार होंगे डिप्टी सीएम, 20 मई को शपथ

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इस सरकार में एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। 20 मई को दोपहर साढ़े बारह बजे बेंगलुरु में शपथग्रहण समारोह होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री के चयन पर मीडिया से बात करते हुए महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक है: हम आम-सहमति में भरोसा रखते हैं, तानाशाही में नहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों कांग्रेस की बड़ी असेट हैं। लोकसभा चुनाव होने तक शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। वहीं हाईकमान के फैसले को लेकर मीडिया के सवाल पर डीके शिवकुमार ने कहा कि सब ठीक है और अच्छा ही होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना है और हमने इसे स्वीकार किया।

बेंगलुरु में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सिद्धारमैया को आधिकारिक रूप से नेता चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मंत्रणा की और फिर सिद्धारमैया और शिवकुमार को इस फार्मूले पर राजी किया गया।

इस फार्मूले पर सहमति बनने के बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार ने गुरुवार को सुबह खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। सूरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर जारी की है जिसमें खड़गे दोनों नेताओं का हाथ पकड़कर ऊपर उठाए हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हम 6.5 करोड़ कर्नाटकाओं से वादा किए गए 5 गारंटी को लागू करेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने दोनों नेताओं के लिए बारी-बारी से ढाई साल के कार्यकाल के फॉर्मूले पर चर्चा की थी। लेकिन शिवकुमार ने इसपर शर्त जाहिर कर दी थी। डीके शिवकुमार ने शर्त रखा था कि अगर यह एक साझा समझौता है तो पहले ढाई साल का कार्यकाल मुझे दिया जाए जबकि दूसरा सिद्धारमैया को। नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए भी डीके शिवकुमार ने मना कर दिया था लेकिन सोनिया गांधी के फोन पर बात करने के बाद शिवकुमार मान गए। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के साथ ही उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपे जा सकते हैं।

हम एकजुट हैं-सिद्धारमैया

बेंगलुरु। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर रस्साकशी जारी थी। एक ओर डीके शिवकुमार थे तो दूसरी ओर सिद्धारमैया थे। आज मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। सिद्धारमैय कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वही डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। डीके शिवकुमार कर्नाटक में इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी उनके हाथ में होगी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के समर्थक भी अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आमने-सामने थे। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्थिति रखा के लिए हमारे हाथ हमेशा एकजुट रहेंगे।

मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है : डीके शिवकुमार

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार प्रमुख दावेदार थे। डीके शिवकुमार को कर्नाटक का उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने से डीके शिवकुमार नाराज हैं? इसको लेकर शिवकुमार को भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, तो हमें निश्चित रूप से खुश होना चाहिए और वादों को पूरा करना चाहिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य, एजेंडा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं परेशान क्यों होऊं? अभी लंबा रास्ता तय करना है। इससे पहले डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फार्मूला बनाया गया है, हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। डीके शिवकुमार का भी एक दृष्टि आया है। इस दृष्टि के जरिए डीके शिवकुमार ने साफ तौर पर कहा है कि हम कर्नाटक भी भारत के लिए एकजुट हैं। अपने दृष्टि में कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं। कर्नाटक के एआईसीसी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हमारा एक ही सूत्र है लोगों की सेवा। जो भी लोगों की सेवा करना चाहता है, वह जितना चाहे कर सकता है। हमारे सभी सहयोगियों की आमंत्रित किया जाएगा (शपथ ग्रहण समारोह में)। यह कोई उत्सव नहीं है, बल्कि लोकतांत्र के लिए कोशिश का समर्पण है। जो लोग लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, वे कांग्रेस में भाग ले सकते हैं।

लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन आज दोनों को लेकर आशंकाओं का यह फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटकों के कल्याण की रक्षा के लिए हमारे हाथ हमेशा एकजुट रहेंगे।

ओडिशा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर बोले प्रधानमंत्री

देश हर राज्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा को कई रेलवे परियोजनाओं का तोहफा दिया है। मोदी ने वर्चुअली पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने पुरी-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के उपहार मिल गए है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षीय भारतीय दोनों का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दिखाई देती है। अब कोलकाता से पूरी जाना हो या पूरी से कोलकाता ये यात्रा सकल लाइव 5 घंटे की हो गई है।

मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने कनेक्टिव से कटिंग बैक्विड इलाकों में भी अपनी रफ्तार की गति को बनाए रखा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज्य की भागीदारी है, देश हर राज्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि मे समय आजादी के अमृतकाल का समय है, भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। मेदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेंई इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और 5.0क भारत-ब्रेड भारत5 की भावना को भी आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खूद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने-कोने में पहुंचा भी रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन, भारत ने अपने बलबूते ही बनाई है।

खेल
प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला आज

धर्मशाला। अभी तक के अपने ज्ञार-चहुत वाले प्रदर्शन के कारण अगर-मगर की कठिन डगर में फंसी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम शुक्रवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करके प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीद बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। इन दोनों टीम के 13 मैचों में समान 12 अंक हैं लेकिन राजस्थान की टीम बेहतर रन रेट के आधार पर पंजाब से आगे है। इन दोनों टीम की हालांकि इस सैच में जीत दर्ज करने के अलावा बाकी टीम के मैचों में भी अनुकूल परिणाम के लिए प्रार्थना करनी होगी। पंजाब की टीम फिर से महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही।

उसके तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले और देथ ओवरों में रन लुटाए जो टीम को भारी पड़े। कैगिसो रबाडा, सैम कुरेन और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों ने लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से रन दिए जिससे टीम पर दबाव बना। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बुधवार को यहां रबाडा अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे। अर्शदीप का उपयोग इस सैच में पावर प्ले और देथ ओवरों में नहीं किया गया जिस पर सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि यह तेज गेंदबाज देथ ओवरों में अपनी यॉर्कर और शुरू में अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करता रहा है। अर्शदीप के प्रदर्शन में हालांकि निरंतरता का अभाव रहा है और इस बरो या मरो वाले मैच में अब उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शिखर धवन ने दिल्ली के खिलाफ 20वें ओवर में बाहर होकर के स्पिनर हरप्रीत बरार का उपयोग किया लेकिन उनका यह दांव नहीं चला और आखिर में मैच में जरूरी इस फैसले ने बड़ा अंतर पैदा किया। बल्लेबाजी में पिछले दो मैचों में रनों का भाव नहीं चल पाए और उन्हें अब आगे बढ़कर नेतृत्व करने की जरूरत है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

आईटीसी का मार्च तिमाही का नेट प्रॉफिट 22.66 फीसदी बढ़ा

नईदिल्ली। विविधि क्षेत्रों में काम करने वाली आईटीसी लिमिटेड का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 22.66 प्रतिशत बढ़कर 5,225.02 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आईटीसी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में 4,259.68 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। आईटीसी की मार्च, 2023 तिमाही में शुद्ध परिचालन आय 19,058.29 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में 17,754.02 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल व्यय मार्च, 2022 में 12,632.29 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2023 में 12,907.84 करोड़ रुपये हो गया। आईटीसी लिमिटेड ने पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में 19,427.68 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया।

मेडट्रॉनिक अपने इंजीनियरिंग, इनोवेशन सेंटर में 3,000 करोड़ रुपये करेगी निवेश

नईदिल्ली। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दुनिया की प्रमुख कंपनी मेडट्रॉनिक पीएलसी यहां मेडट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर (एमईआईसी) के विस्तार के लिये 3,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। मेडट्रॉनिक ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एमईआईसी कंपनी का अमेरिका के बाहर यह सबसे बड़ा शोध एवं विकास केंद्र है। यह कंपनी का वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं विकास आधारित नवोन्मेष तथा वृद्धि रणनीति का हिस्सा है। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी राम राव से अमेरिका के न्यूयार्क में मुलाकात की। एमईआईसी में वर्तमान में 800 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नये निवेश की घोषणा के साथ अगले पांच साल में यह संख्या 1,500 से अधिक होने की उम्मीद है।

भारत में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी एमेजॉन वेब सर्विसेज

नईदिल्ली। एमेजॉन की एमेजॉन वेब सर्विसेज भारत में 1270 करोड़ डॉलर यानी 1.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने हाल ही में इसका ऐलान किया है। कंपनी द्वारा जारी बयान के बता मुताबिक इस निवेश से भारत में विस्तार होने वाले सर्विसेज की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसके चलते एमेजॉन वेब सर्विसेज साल 2023 तक देश के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। अगर भारत में ये निवेश होता है तो इससे भारतीय कारोबार में हर साल औसतन 1,31,700 फुल टाइम के बराबर रोजगार के मौके तैयार होंगे। क्लाउड सर्विसेज के अंतर्गत इसमें कंप्टस्वान, फैसिलिटी मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और अन्य सेगमेंट के जॉब शामिल हैं जो भारत में डेटा सेंटर सपर्ब्ड चेन का हिस्सा है। वेब सर्विसेज के बयान के अनुसार, '2030 तक इसका भारत में निवेश 1.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।'

कच्चे तेल के दाम में 0.13 प्रतिशत की गिरावट

नईदिल्ली। वायदा बाजार में कच्चा तेल का भाव 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,027 रुपये प्रति बैरल रहा। कमोडेर मोंग के बीच सटीरियों के सौदा कम किये जाने के कच्चे तेल के दाम में नरमी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव आठ रुपये यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,027 रुपये प्रति बैरल रहा। इसमें 7,211 लॉट के लिये कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72.60 डॉलर प्रति बैरल रहा। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.72 डॉलर प्रति बैरल रहा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत

गतांक से आगे...

प्रह्लाद सवनानी

भारत में 5जी और 6जी तकनीक का विकास देखने जी-20 समूह के सदस्य देशों की एक टीम भारत के आईआईटी संस्थानों में भी गई है। भारत में डिजिटल क्रांति से समूह के सदस्य देश प्रभावित हुए हैं कई सदस्य देशों ने तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है एवं इस तकनीकि को यह देश अपने यहां भी लागू करना चाह रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर, अब बहुत सफल तरीके से कार्य कर रहा है। यूपीआई ने 376 बैंकों को अपने साथ जोड़ लिया है और इस प्लेटफोर्म पर 11.9 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेनदेन किए जा रहे हैं। जुलाई 2015 में भारत ने 'डिजिटल इंडिया' पहल की शुरुआत की थी और आज इस स्थिति तक पहुंच गया हैं।

याद कीजिए भारत में एक दौर हुआ करता था जब सामान्य नागरिक उपचार खरीदने के लिए दुकानों में जाया करते थे। बेहतर विकल्प की तलाश एवं कम कीमत पर सामान खरीदने के उद्देश्य से एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान के चक्कर लगाते थे। उपचारों की खरीद के पूर्व बैंकों में जाकर राशि निकालनी होती थी, ताकि नकद राशि अंदर उपचार खरीदे जा सकें। परंतु भारत में डिजिटल क्रांति के बाद अब नागरिक विभिन्न उपचार यंत्र जिन्हाएँ में खरीद लेते हैं, वह भी मोबाइल फोन पर। कल्पना कीजिए कि आज देश में एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए यदि 6 से 8 घंटे का समय बचा रहा है तो 140 करोड़ की आबादी कितना समय बचा पा रही है। बचाए गए इस समय का सार्थक उपयोग किया जाकर देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे 'डिजिटल इंडिया' को भी सहारा मिलेगा और वैसे भविष्य के आर्थिक सफर को बुनियाद भी यही है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते बैंक जो जैसे नागरिकों की जेब में समा गई है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल की सुविधा से नागरिक 24 घंट × साल दिन, रुपए को अपने खाते से दूसरे के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफोर्म्स पर उपयोगी की कीमत एवं गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर उपयुक्त की खरीद सकते हैं। साथ ही, यह सुविधा तो अब देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध हो गई है।

बैंकिंग सुविधाओं को नागरिकों को प्रदान करने के मामले में तो भारत यूपीआई के माध्यम से बहुत आगे निकल आया है और आज यूरोपीयन विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए भारत में काफी समय से मेहनत से काम किया गया है। आॅप्टिकल केबल का जाल गांवों तक बिछाया गया है, 5ज की तकनीकी आने के बाद इसे भी देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में से जाया जा रहा है, ब्रॉडबैंड की सुविधा को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, ताकि इंटरनेट की उपलब्धता गांव स्तर तक बनी रहे। ग्रामीणों को इन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किए जाने के प्रयास भी किया गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान ही चलाया कि डिजिटल प्लेटफोर्म पर किस प्रकार बैंकिंग व्यवहार किए जाने चाहिये। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते करोड़ों नागरिकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सब्सिडी आदि का पैसा भी सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाता है, जिससे आय के रिसन को पूर्णतः समाप्त कर लिया गया है। जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते, आधार कार्ड एवं मोबाइल को जोड़कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही, अधिकतम सरकारी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफोर्म्स पर लाया जा रहा है ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। भारत में पिछले 9 वर्षों के दौरान किए गए कई आर्थिक उपायों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन तेज़ गति से पटरी पर दौड़ने लगा है।

कांग्रेस के भाग्यशाली अध्यक्ष साबित हो रहे खड़गे

हरीश गुप्ता

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आने शुरू हुए थे तो तीनों गांधी (सोनिया, राहुल और प्रियंका) की नजरें टीवी की ओर ही लगी हुई थीं। राहत के उन क्षणों में सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयासों की सराहना की थी, जिन्होंने 36 जनसभाओं को संबोधित किया था। 10 जनपथ के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो प्रियंका ने यह कहते हुए अपनी मां को बधाई दी थी कि उनके द्वारा चुना गया सेनापति कामरेड भाग्यशाली रहा है। प्रियंका ने सही कहा था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के आठ माह के भीतर ही खड़गे ने दो राज्यों में पार्टी को जीत दिलाई है। खड़गे के 26 अक्टूबर 2022 को पदभार संभालने के बाद पार्टी ने हिमाचल में जीत दर्ज की। लंबे सूखे के बाद 8 दिसंबर 2022 को पार्टी द्वारा दर्ज की गई यह पहली जीत थी। उसके पांच माह बाद, 13 मई 2023 को खड़गे ने कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य गांधी परिवार को सौंपा है। कर्नाटक में खड़गे की अनिरपरीक्षा थी क्योंकि यह उनका गृह राज्य था। दूसरे, 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बावजूद गांधी परिवार ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊपर उठाई थी। उन्होंने अनेक समीकरणों को साधते हुए कठोर परिश्रम किया और कुछ कठोर फैसले भी लिए। भाजपा नेतृत्व को इस वास्तविकता को समझने में बहुत देर लगी कि राज्य में खड़गे दलितों और मुस्लिमों को एक साथ लाने में उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं। यह भाजपा के लिए घातक साबित हुआ क्योंकि सिद्धारमैया के साथ प्रतिद्वंद्विता और डी.के. शिवकुमार के कारण बोम्मलिंग पाटिल से ही कांग्रेस के साथ जुड़े थे। यह डी.के. शिवकुमार ही थे जिन्होंने देवगौड़ा के तीन दशक पुराने किले को ढहाने में सफलता पाई। खड़गे भाजपा के लिए भारी साबित हो सकते हैं क्योंकि वे विशिल्प एक नए दलित नेता के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि पिछले 30-35 वर्षों में बड़े पैमाने पर दलित वर्ग के पुरुष दलों में जा चुके दलित वोटों को वह फिर से अपने पाले में ला सकती है। मायावती और ओवैसी की पार्टी जैसे दूसरे दलों में जा चुके मुस्लिम भी उन सीटों पर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं जहां वह भाजपा को हराने की स्थिति में हो। भाजपा पर कर्नाटक की भारी हार का असर नजर आने लगा है। राजाबद्ध पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद बीएमसी चुनाव कराने का मन बना लिया था। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और अन्य नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे जहां शाह ने उनसे हर म्युनिसिपल वार्ड में आक्रामक तरीके से काम शुरू करने को कहा था। ठाकरे से बीएमसी को छीनने के लिए शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को सात सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भले ही शिंदे सरकार को बरकरार रखकर राहत दी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अन्य मंचों पर कानूनी लड़ाई आने वाले दिनों में लंबी चलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुंबई का दौरा किया था। लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने योजना को अधर में लटका दिया है। मुंबई-कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा बुरी तरह पराजित हुई है जहां अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। भाजपा की सिर्फ कर्नाटक में ही हार नहीं हुई है बल्कि पंजाब में भी जालंधर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में उसके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस उपचुनाव में उसके वोट शेयर में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन भाजपा के इकबाल सिंह अटवाल न सिर्फ चौथे स्थान पर रहे बल्कि अपनी जमानत भी गंवा बैठे। उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाने के लिए डाले जाने वाले कुल वैध मतों का छठवां हिस्सा हासिल करना होता है। लेकिन भाजपा उम्मीदवार ऐसा कर पाने में विफल रहे। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की यह दूसरी हार है। भगवा पार्टी ने लेकिन विपक्षियों के मुद्दे पर अपने तीन दशकों के विश्वस्त सहयोगी को खो दिया था। अब लोकसभा चुनावों को नजदीक आते देख भाजपा नेतृत्व फिर अकाली दल से गठजोड़ कर सकता है। अकाली दल का उम्मीदवार भी जालंधर उपचुनाव में पराजित हुआ है लेकिन पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल खुश हैं क्योंकि अकाली दल का उम्मीदवार आप और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि शिअद-भाजपा की एकता परिदृश्य को बदल सकती है। लेकिन बादल अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं हैं और अनुकूल मौके की राह देख रहे हैं।

गहलोत की चाल से पायलट-वसुंधरा पस्त

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपने संबंधों को लेकर खुलासा क्या किया वसुंधरा राजे उनसे पहले ही परेशान नजर आने लगी हैं। राजस्थान में पिछले 25 वर्षों से एक बार सोनिया गांधी तो दूसरी बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। इस बार वसुंधरा राजे फिर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। मगर अशोक गहलोत ने बयान देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

हाल ही में धौलपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलासा किया था कि 2020 में सचिन पायलट द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ बगावत करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उनके समर्थक विधायकों ने सहयोग कर उनकी सरकार को गिरने से बचाया था। गहलोत ने कहा था कि धौलपुर से भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर खुले आम पार्टी नेतृत्व की अनदेखी की थी। शोभा रानी कुशवाहा वसुंधरा समर्थक विधायक मानी जाती रही हैं। इसके साथ ही गहलोत ने वसुंधरा समर्थक मानने जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का भी नाम लिया था।

विधानसभा में बजट पास करवाने के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में 17 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। जिसमें उन्होंने कैलाश मेघवाल के विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा को भी जिला बनाया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैलाश मेघवाल को शाहपुरा के जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा था कि आप की मांग पूरी कर दी गई है। उस समय भी गहलोत के बयान की काफी चर्चा हुई थी तथा भाजपा बैकफुट पर आ गई थी।

राजस्थान की राजनीति में लोगों की धारणा रही है कि अंदर खाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। इसी के चलते जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं और जब भाजपा की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाती हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते दोनों नेता एक दूसरे के हितों का खयाल रखते हैं तथा जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल तो खुलकर यह आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी गहलोत को पत्र लिखकर वसुंधरा सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि एक माह पूर्व सचिन पायलट ने अपनी इसी मांग को लेकर जयपुर में एक दिन का धरना भी दिया था। इसके बाद पायलट ने इसी मांग को लेकर 5 दिनों तक अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की जन संपर्क पदयात्रा भी की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वसुंधरा राजे को लेकर किए गए खुलासे के बाद वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर के निशाने पर आ गई हैं। राजस्थान में वसुंधरा विरोधी खेमे के नेता गहलोत के बयान को लेकर मखर हो रहे हैं। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों के दम पर ही गहलोत बेखौफ होकर सरकार चला रहे हैं। राजस्थान में पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान कई वसुंधरा समर्थक विधायकों को मतदान से पहले गुजरात भेजा गया था ताकि वह गहलोत के प्रभाव में आकर क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकें।

हालांकि राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे सबसे बड़े कद के नेता मानी जाती हैं। दो बार प्रदेश की मुख्यमंत्री, तीन बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा वर्तमान में लोकसभा सांसद

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने दी कबीर आश्रमों में विभिन्न कार्यों के लिए 40 लाख रुपये की मंजूरी

धमतरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के कबीर समाज को विभिन्न कार्यों के लिए 40 लाख रूपए की मंजूरी दी है। कबीर विश्व शांति मिशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह मंजूरी बुधवार को धमतरी विश्रामगृह मोत्रे में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रमुखो से चर्चा के दौरान दी। गौरतलब हैं कि कबीर समाज द्वारा हुए कबीर संस्थान धमतरी और देवपुर बाचनालय में फर्नीचर स्टाक एवं साहित्य, कबीर संस्थान धमतरी के सौंदर्यीकरण भवन विस्तार एवं स्थापत्य रोट, कबीर आश्रम सेंचुवा में सत्संग शेड निर्माण, कबीर आश्रम कलारहाई सत्संग निवास भवन और कबीर आश्रम सेमरा में भवन निर्माण एवं शौचालय निर्माण के लिए कुल 40 लाख रुपये की मांग की गई थी।

सामाजिक भवन के लिए पदमशाली समाज को लीथम ने दिया 25 लाख

धमतरी। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में धमतरी पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पदमशाली समाज का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस बीच समाज के अध्यक्ष संजीव आड़ेपवार ने मुख्यमंत्री को सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए सामाजिक भवन निर्माण की जरूरत बताई, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने पदमशाली समाज को सहृदयता से सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष संजीव आड़ेपवार, यशवंत पेनकोंडवार, विजय पदमवार, अजय कनपल्लीवार, अनंत पदमवार, पूरनदेव नाड़ेम शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पदमशाली समाज आज करीब ढाई सौ साल पहले आंध्रप्रदेश से यहां आकर बसे हैं। ईष्ट देव भगवान मारकंडेय के वंशज पदमशाली समाज आज सामाजिक एकता और रचनात्मक कार्यों के जरिए शहर में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज की ओर से भवन निर्माण की स्वीकृति में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल, पूर्व विधायक गुरूमुख सिंह होरा, जिलाध्यक्ष शरद लोहारा, महापौर विजय देवांगन, मोहन लालवानी, आनंद पवार का आभार व्यक्त किया है।

ग्राम कनेचूर लेम्पस गोदाम में भंडारित खाद उर्वरक का लिया गया सैम्पल

कांकेर। विकासखंड भानुप्रतापपुर के बैजनपुरी सहकारी समिति लेम्पस अंतर्गत ग्राम कनेचूर गोदाम में भंडारित रासायनिक उर्वरक डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट खाद का बीज एवं उर्वरक निरीक्षक निरंजन नरेटी द्वारा सैम्पल लिया गया। इस दौरान खाद के लिए लेम्पस पहुंचे किसानों को उर्वरक निरीक्षक द्वारा समझाइश देते हुए कहा कि लेम्पस में भंडारित रासायनिक खाद बीज का खरीफबुवाई के पूर्व ही अग्रिम उठाव करें, ताकि लेम्पस गोदामों में स्टॉक के रख-रखाव और वितरण में आसानी हो सके। किसानों को रासायनिक खाद का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करने और साथ ही लेम्पसो में भंडारित वर्मी कम्पोस्ट खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई। इसके अलावा दानेदार यूरिया के कमी को दूर करने यूरिया के विकल्प के रूप में लेम्पस में भंडारित नैनो तरल यूरिया बॉटल का भी उठाव एवं उपयोग करने की सलाह किसानों को दी गई। लेम्पस के निरीक्षण के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रविण कवाची, लेम्पस कर्मचारी नीलेश नाग, हेरा कुमेरी, हर्ष साहू एवं कृषकगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में सुस्त हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 41 नए मरीज मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के कम मरीज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 2533 सैम्पलों की जांच की गई है। इस दौरान औसत पॉजिटिविटी दर 1.62 प्रतिशत रही। आज सबसे ज्यादा 12 नए मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं। इसके अलावा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेशभर से 69 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज/रिकवर हुए हैं। आज नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में सक्रीय कोरोना संक्रमितों की तादाद घटकर 309 रह गई है। कबीरधाम से 1, बलरामपुर से 1, सरगुजा से 1, सुकमा से 1, सूरजपुर से 2, महासमुंद से 2, राजनांदगांव से 2, कांकेर से 2, बलौदाबाजार से 3, दंतेवाड़ा से 4, बालोद से 5, दुर्ग से 5, रायपुर से 12 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है।

आज शनि महोत्सव, होंगे विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम

दुर्ग। श्री मनोकामना सिद्ध गजकेसरी शनि शक्तिधाम में शनि जयंती महोत्सव 19 मई को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रातः 4 बजे पंच नदियों के जल सहित, गंगा जल, गुलाब जल, पंचोपचार षोड़षोपचार पूजन और फिर विशुद्ध सरसों के तेल द्वारा लगातार शुक्ल यजुर्वेदीय वैदिक मंत्रों से तेलाभिषक किया जाएगा। प्रातः 5 बजे सर्वबाधा निवारक नवग्रह 19 मई को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रातः 4 बजे पंच नदियों के जल सहित, गंगा जल, गुलाब जल, पंचोपचार षोड़षोपचार पूजन और फिर विशुद्ध सरसों के तेल द्वारा लगातार शुक्ल यजुर्वेदीय वैदिक मंत्रों से तेलाभिषक किया जाएगा। प्रातः 5 बजे सर्वबाधा निवारक नवग्रह 19 मई को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रातः 4 बजे पंच नदियों के जल सहित, गंगा जल, गुलाब जल, पंचोपचार षोड़षोपचार पूजन और फिर विशुद्ध सरसों के तेल द्वारा लगातार शुक्ल यजुर्वेदीय वैदिक मंत्रों से तेलाभिषक किया जाएगा। प्रातः 5 बजे सर्वबाधा निवारक नवग्रह

युवाओं को प्रकृति बचाने आगे आने का आह्वान

व्यक्तिगत व्यवहार व आदतों का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव विषय पर वाद-विवाद एवं युवा संसद का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, नवा रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में व्यक्तिगत व्यवहार व आदतों का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव विषय पर वाद-विवाद एवं युवा संसद का आयोजन कलिंगा विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. श्रीधर ने किया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर कुलपति डॉ. श्रीधर ने प्रकृति को बचाने के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अनिता सावंते ने कहा कि वर्तमान में हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाते हुए उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने की जरूरत है।

मण्डल के जनसंपर्क अधिकारी, श्री अमर प्रकाश सावंत ने कहा कि हमें प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग से बचना चाहिए और कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय, अमेटी विश्वविद्यालय, आई.आई.आई. टी., नवा रायपुर, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय एवं भिलाई इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुल 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन कर इन्हें ईस्ट जोन की प्रतियोगिता के लिए नई दिल्ली भेजा जाएगा। जहां यह प्रतियोगिता 01 से 02 जून को आयोजित की जाएगी।

किसानों को दी गई उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की जानकारी

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर एवं रोहृा बागवानी बोर्ड, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं उद्यानिकी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। कृषि विज्ञान केन्द्र एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मिलकर किस प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में किसानोन्मुखी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. गौतम रॉय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, रायपुर के उपनिदेशक, श्री एस.के. शर्मा, उपसंचालक, उद्यानिकी रायपुर, श्री कैलाश पैकरा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के पूर्व कुलपति, डॉ. नरेन्द्र दीक्षित उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. एस.एस. टुटेजा ने विश्वविद्यालय द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। कार्यक्रम के अन्य अतिथियों ने भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं उद्यानिकी योजनाओं के संबंध में किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित तकनीकी सत्र में किसानों को उक्त पोष सामग्री उत्पादन तकनीक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी साथ ही साथ इन पौष सामग्रियों का विपणन किस प्रकार से किया जाना चाहिए इस पर चर्चा भी हुई। किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से उद्यानिकी फसलों का उत्पादन एवं विपणन वृहद पैमाने पर कैसे किया जा सकता है इस विषय पर किसानों एवं वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर एवं सब्जी विज्ञान विभाग द्वारा खुला परागण एवं संकर बीज उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विधायक देवेंद्र यादव होंगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव, होरा का इस्तीफा मंजूर

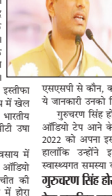

रायपुर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए महासचिव को लेकर जारी जद्दोजहद अब थम चुका है। भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव छत्तीसगढ़ ओलिम्पिक संघ के नए महासचिव होंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने भारतीय ओलिम्पिक संघ को अध्यक्ष पीटी उषा को भी जानकारी भेज दी है।

प्रदेश में केवल तीन व्यवसाय में एकाधिकार को लेकर एक आंडिया वायरल हुआ था। इसमें बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। कथित आंडियो में होरा सीएम भूपेश के नाम का प्रयोग दलाल बनाने के लिए कर रहे थे। इतना ही नहीं इसमें दावा किया गया था कि अफसर उनको रिपोर्ट देते रहते हैं। कलेक्टर और एसएसपी से कौन, क्या बात कर रहा है, ये जानकारी उनको मिलती रहती है।

गुरचरण सिंह होरा ने इस विवादित आंडियो टेप आने के बाद 20 सितम्बर 2022 को अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्यगत समस्या बताई थी।

गुरुचरण सिंह होरा ने इस्तीफा देना मुनासिब समझा

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव पद से अंततः गुरुचरण सिंह होरा ने इस्तीफा देना उपयोगी समझा, कथित आंडियो टेप में उछला था होरा का नाम तब से उनकी विदाई तय मानी जा रही थी। इस बीच पुराने साथी बशीर अहमद खान से भी उनकी खटपट हो गई। कुछ मामलों को लेकर वे न्यायालय तक भी पहुंच गए थे। पिछले दिनों भिलाई में ओलिंपिक संघ की बुलाई गई बैठक में विधायक देवेन्द्र यादव को नया महासचिव भी घोषित कर दिया गया जो अध्यक्ष भूपेश बघेल के विश्वसनीय माने जाते हैं। होरा ने अलग से बैठक बुलाने की बात कही हुए नाराजगी जाहिर तो की लेकिन जब देखा कि पूरी तरह अलग-थलग पड़ चुके हैं तो उन्होंने इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष की हैसियत से उनका इस्तीफा स्वीकृत कर दिया है। इसकी जानकारी भारतीय ओलिम्पिक संघ को भी भेज दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन

साढ़े चार साल में 737 इकाईयों में 1398 करोड़ का हुआ निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप राज्य में पिछले साढ़े चार सालों में 737 नई इकाईयों स्थापित हुई है। इन इकाईयों में 1397 करोड़ 24 लाख रूपए का पूंजी निवेश हुआ है और 6 हजार 896 लोगों को रोजगार मिला है।

मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी विकास कार्यों को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रूपए) तक अनुदान, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रूपए) तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रूपए की राशि तक का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (2.50 करोड़ रूपए अधिकतम) तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कुलिंग की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रूपए) तक का अनुदान अग्रिमयों को प्रदाय किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुदान शर्तों में आवेदक की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए यानी आवेदक का नेटवर्थ आवेदन किये गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावों का बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सावधि जमा का लाभ उठाया जाना चाहिए, सावधि ऋण परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

बैंक व वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किये जाने चाहिए, जिनके लिए अनुदान मांगा गया है। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए निर्धारित घटकों में से किन्ही 2 परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी।

शान्ति सरोवर में आज से तीन दिवसीय जिन्दगी का उत्सव-शिविर

रायपुर। प्रज्ञापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा विश्वनाथ्था मार्ग स्थित शान्ति सरोवर में 19 से 21 मई तक जिन्दगी का उत्सव नामक तीन दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में मेमोरी मैनेजमेन्ट, तनाव प्रबन्धन की कला और राजयोग मेडिटेशन सहित स्वस्थ जीवन हेतु उपयोगी अन्य व्यवहारिक बातों की जानकारी दी जाएगी।

यह शिविर माउण्ट आबू के जाने माने इन्टरनेशनल हाईवे इस्ट माइण्ड व मेमोरी मैनेजमेंट ट्रेनर और वर्ल्ड रिकार्ड होल्डर ब्रह्माकुमार शक्तिराज सिंह के मार्गदर्शन में प्रतिदिन दो सत्रों में सुबह एवं शाम को ठीक 7.00 बजे आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपनी सुविधानुसार किसी एक सत्र में भाग लेना जरूरी होगा। प्रवेश निशुल्क रखा गया है।

इस शिविर का उद्देश्य मन की अद्भुत शक्ति का विकास करना है। मन की शक्ति द्वारा सिरदर्द, डायबिटिज, ब्लड प्रेशर, एसीडिटी, अस्थमा आदि रोगों पर विजय पाया जा सकता है। शिविर में प्रशिक्षित अनेक आध्यात्मिक विषयों पर गहन चर्चा होगी। जिनमें से प्रमुख हैं - अनमोल में छिपे लोहार की खोज, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए राजयोग, मन का सकारात्मक प्रबन्धन, परीक्षा के भय से मुक्ति, तनाव और क्रोध से मुक्ति के उपाय, शरीर से अलग दिव्य अनुभव, परम सत्य की पहचान तथा राजयोग मेडिटेशन द्वारा मनोबल, एकाग्रता और आत्म विश्वास में वृद्धि आदि।

गौरतलब है कि ब्रह्माकुमार शक्तिराज सिंह जाने-माने इन्टरनेशनल माईण्ड व मेमोरी मैनेजमेन्ट प्रशिक्षक होने के साथ ही प्रतिभाशाली वक्ता हैं। यह विश्व के एकमात्र ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने मात्र 31 वर्ष की आयु में बारह राज्य से भी ज्यादा लोगों को माइण्ड व मेमोरी की आध्यात्मिकता के आधार पर निशुल्क ट्रेनिंग दी है। अनेक प्रशिक्षित संस्थानों में हजार से भी ज्यादा व्याख्यान दे चुके हैं। उनके व्याख्यान आस्था, संस्कार और पॉस ऑफ माइण्ड चैनलों में निरन्तर प्रसारित होते ही रहते हैं।

अग्रवाल सभा की युवा इकाई ने देखी केरला स्टोरी

रायपुर। अग्रवाल सभा रायपुर की युवा इकाई के 350 सदस्यों ने युवतियों को जागृत रखने के लिए बनाई गई फिल्म केरला स्टोरी देखने के लिए पीवीआर मैनेटो मॉल पहुंचे। इस दौरान अग्रवाल समाज एवं भूपतिया परिवार ने सभी को हनुमान चालीसा का किताब भेंट किया। प्रसार प्रमुख आयुष मुरारका ने बताया कि युवतियों को जागृत रखने के लिये बनाई गई फिल्म केरला स्टोरी को एक बार सभी को देखनी चाहिए खासकर हमारी युवा पीढ़ी के बच्चों को। फिल्म में यह बताया गया है कि हमें गलत संगत से बचना बहुत आवश्यक है, अगर हम बुरे संगत में फंस गए तो उससे निकल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल सभा रायपुर की युवा इकाई ने अपने 350 सदस्यों को निशुल्क यह फिल्म दिखाया, खासकर समाज की युवतियों जो बाहर से आकर यहां पढ़ रही हैं उन्हें विशेष रूप से बुलाया गया था। फिल्म के समापन के बाद अग्रवाल समाज एवं भूपतिया परिवार के सदस्यों ने मिलकर केरला स्टोरी देखने आए सभी लोगों को हनुमान चालीसा का किताब निशुल्क भेंट किया। इस अवसर पर अग्रवाल युवा मंडल के अध्यक्ष राम अग्रवाल, महामंत्री सौएस सौरभ अग्रवाल, युवती मण्डल अध्यक्ष शिवांगी अग्रवाल, सेकेटरी स्वाति अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक आशीष अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल,अमर अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, कंचन अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

नहीं हुई थी किडनी चोरी, कब्र से शव निकालकर किया गया पोस्टमार्टम

■ परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया था आरोप

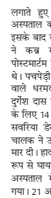

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करीब एक माह पहले सड़क हादसे में घायल हुए अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर किडनी चोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र खोदकर अधेड़ का शव निकाला गया और गुरुवार को पोस्टमार्टम हुआ। इसमें पुष्टि हो गई है कि किडनी चोरी नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु के शव में दोनों किडनियां मिली हैं। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, सड़क हादसे में मारे गए ग्राम सोन निवासी धरमदास मानिकपुरी के शव का सिम्स अस्पताल की मॉर्चुरी में पोस्टमार्टम किया गया है। एक्सपर्ट की निगरानी में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मृतक धर्मदास मानिकपुरी के परिजनों ने 21 अप्रैल को किडनी चोरी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से प्रार्थना अस्पताल की शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए थे। पचपेड़ी के ग्राम सोन में रहने वाले धरमदास मानिकपुरी और दुर्गेश दास शादी का कार्ड बांटने के लिए 14 अप्रैल को निकले थे। सबरिया डेरा के पास स्कॉर्पियो चालक ने उनको बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 21 अप्रैल को धरमदास की मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटे ने कलेक्टर और पुलसी से शिकायत की। इसमें आरोप लगाया कि पिता के पेट पर चाप मारा हो, आशंका है कि डॉक्टरों ने किडनी निकाल ली है।

धमतरी में 23 सब इंजीनियरों को मुख्यमंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र

■ लम्बे इंतजार के बाद नियुक्ति आदेश जारी होने से उत्साहित सब इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति जताया आभार

धमतरी। प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों पर भर्तियों की जा रही है। जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को शासकीय सेवा के अवसर प्राप्त हुए है। जल संसाधन विभाग द्वारा भी 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति हुई है। धमतरी में पदस्थ हुए 23 उप अभियंताओं ने धमतरी में ग्राम भटगांव में भेंट-मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उनके प्रति आभार जताया। युवाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विभाग में नियुक्ति होने से युवाओं का हौसला बढ़ा है और वे सभी मन लगाकर बढ़िया कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग खेती-किसानी और आम-आदमी की पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को देखते हुए इस विभाग में अधोसंरचना विकसित करने करने की बड़ी गुंजाइश है। आप सभी खूब मेहनत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्तियां हों। युवाओं को शासकीय सेवा में काम करने का अवसर मिले। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरियों में भर्ती का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती के लिए लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, इसी प्रकार जहां चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, वहां नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं।

लम्बे इंतजार के बाद नियुक्ति आदेश प्राप्त होने से उत्साहित जल संसाधन विभाग के चयनित उप अभियंताओं ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा नये उप अभियंताओं की भर्ती करने से जहां एक ओर उनके करियर को स्थायित्व मिला है। वहीं परिवार वालों के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं साथ ही परिवार की आर्थिक जरूरतों भी पूरी होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चयनित सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में आने का आपका और आपके परिवार का सपना पूरा हुआ है। अब हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ को जनता के सपनों को साकार करना है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग में भी काफी दिनों बाद इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरों की भर्ती की गई है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को खेतों तक पानी पहुंचाने के साथ उद्योगों को पानी की आपूर्ति तथा पेयजल व्यवस्था को भी ध्यान रखना है, इसके लिए आप लोगों से जनता को बड़ी आशाएं हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंता के 400 पदों पर जल संसाधन विभाग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण के बाद चयनित 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 48 पदों पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं जिले में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 23 उप अभियंताओं की पदस्थापना की गयी है।

जल संसाधन विभाग में नियुक्ति पाने से उत्साहित जुनियर इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जल संसाधन विभाग के नव नियुक्त उप अभियंता विनीत सुनाकर ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर का निवासी होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में परेशानी होती थी, जिससे रोजगार के अवसर कम मिल पाते थे।

पीएससी के नतीजों पर सवाल भाजपा की स्तरहीन राजनीति

कांग्रेस ने 2018 के पहले चयनित नेताओं, अधिकारियों तथा आपसी रिश्तेदारों की सूची जारी की

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के परीक्षा परिणाम आये है हम चयनित युवाओं को बधाई और शुभकामनायें देते है। दुर्भाग्य से भाजपा अपनी निम्नस्तरीय राजनीति के लिये इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही हम इसकी कड़ी निंद्य भी करते है।

यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर इस प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति राज्य लोकसेवा आयोग की चयनित सूची पर सवाल खड़ा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और डॉ. रमन सिंह बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहे कि पीएससी में, नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों के कुछ नाम चयनित हो गये है। रमन सिंह और भाजपा को आपत्ति है कि चयनित बच्चों में भाई-बहन, पति-पत्नी, अधिकारियों के बच्चें चयनित हो गये? मैं आपके समक्ष एक सूची सामने रख रहा हूं जो भाजपा के शासनकाल में चयनित हुये है कि पीएससी में, नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों के कुछ नाम चयनित हो

आरोप लगा रहे, एक राजनीतिक दल के रूप में हम अपनी राजनीतिक जवाबदारी को समझते है। हमारा यह सूची जारी करने का आशय इतना मात्र है कि पहले भी नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों को प्रशासनिक सेवा में चयन होते रहा है लेकिन किसी का किसे नेता अधिकारी का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं हो जाती है। (सूची-ए संलग्न)

आंसरशीट जारी हो गया है पब्लिक डोमेन में है। सबके टिटेन के नंबर और इंटरव्यू के नंबर ओपेन है कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है लोग अपने राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने मेहनती प्रतिभावान बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे।

मैं आपके समक्ष इस वर्ष चयनित 21420 अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें साफ है कि अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, लिखित में कितने नंबर मिले। (सूची-बी संलग्न)

रमन सिंह अपने पन्द्रह साल के कार्यकाल में पीएससी की बिना विवाद के पन्द्रह परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा पाये वो आज कौन से मुंह से युवाओं के भविष्य की बात करते है?

रमन सिंह के पिछले डेढ़ दशक के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल घ्रष्टाचार और अनियमितता का अड्डा बन चुका था।प्रदेश की जनता अभी भूली नही है पीएमटी परीक्षा के प्रश्न पत्र रमन राज में 2011 में बाजारों में बिके थे। भाजपा का नेता मुंगेली में पीएमटी परीक्षा में सामूहिक नकल करवाते पकड़ाया था देश के किसी भी व्यवसायिक परीक्षा मंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही परीक्षा को एक वर्ष में चार बार करने की नौबत आयी हो। छत्तीसगढ़ में तो तीन बार परीक्षायें उसी परीक्षा नियंत्रक के देख-रेख में आयोजित की गयी जो प्रथम दृष्टया दो बार परीक्षा की गड़बड़ी के लिये दोषी था।व्यवसायिक परीक्षा मंडल में तत्कालीन नियंत्रक वी.पी. विपाठी की नियुक्ति किसके इशारे पर की गयी? विपाठी को नियुक्ति के लिये जो नोटशीट सरकारी महकमे में चली थी उसमें तत्कालीन मुख्य सचिव शिवराज सिंह के द्वारा विपाठी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने तथा उसकी नियुक्ति किये जाने को अनुचित बताये जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने क्यों विपाठी की नियुक्ति का अनुमोदन किया था?

तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक वी.पी.विपाठी को रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा स्केल लिस्टेड घोषित किया गया था उसे रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा गोपनीय कार्यों से अलग रखा गया था ऐसे दागी अधिकारी को व्यवसायिक परीक्षा मंडल का नियंत्रक बनाया था।

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष रहे एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को उनके कार्यकाल में प्रदेश के वरिष्ठ प्रभावशाली नेता के परिजनों द्वारा 25 छात्रों की सूची पी.एम.टी. में चयन के लिये दी गयी थी। उन्होंने यह कृत्य करने से मना कर दिया तो सेवानिवृत होने के बाद उस अधिकारी के जायज देयकों को रोक दिया गया।

पीएमटी परीक्षा की गड़बड़ियों के तार तत्कालीन सत्ता शीर्ष के करीबियों तक जब जुड़ने लगे तो अपनी को बचाने इस कांड की चांच को बंद करवा दिया गया, दोषियों को भी बख्श दिया गया था।बच्चों पर केस बना दिया गया लेकिन दोषी अधिकारी, कर्मचारी और पर्दे के पीछे सारा खेल-खेलने वाले रसूखदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

जो लोग पहले घ्रष्टाचार करते थे वे आज पारदर्शी चयन पर सवाल खड़ा कर रहे है।

पत्रकार वार्ता में महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, अजय गंगवानी उपस्थित थे।

सीएम बघेल से सुप्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा ने सौजन्य मुलाकात की। देवी चित्रलेखा से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ में गौ-माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाई जा रही गोधन न्याय योजना की जानकारी दी। देवी चित्रलेखा ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल को खुद की लिखी हुई श्रीमद् भगवद् गीता की पुस्तक भी भेंट की।

मुख्यमंत्री ने देवी चित्रलेखा को बताया की हमारी सरकार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों के माध्यम से गोधन न्याय योजना का संचालन कर रही है। इस योजना में 2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। इससे गौ वंश की सुरक्षा के साथ साथ गौपालकों एवं आम लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने उन्हें गौठानों में गोबर से बनाए जाने वाले उत्पादों को भी जानकारी दी और बताया की गौठन कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त मॉडल बनकर कर उभर रहे हैं।

देवी चित्रलेखा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी संस्था के द्वारा हरियाणा के पलवल जिले में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस संस्था में गौ-माता की सेवा, संरक्षण और इलाज किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री माधव तिवारी, श्रीमती पुष्पा तिवारी और श्री पुनीत गौर भी मौजूद थे।

छह माह पहले ही बृजमोहन ने संभाला चुनावी मोर्चा

■ अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में शुरू किया जनसंपर्क अभियान

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दक्षिण विधानसभा में छह माह पहले ही चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। वैसे वे अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों व लोगों से सतत संपर्क में निरंतर रहते हैं लेकिन वार्ड में निर्धारित कार्यक्रम बनाकर सघन जनसंपर्क अभियान जिस अंदाज में शुरु किया गया है माना जा रहा है चुनाव से पहले ही वे पूरे क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू हो जाना चाहते हैं। अभियान की शुरूआत बुधवार को विभिन बिहारी गुरु वार्ड से की गई। इस बीच कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। नागरिकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। कुछ जगहों पर नुकड़ सभाएं लीं और उस दिन का समापन वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लेकर की।

इस बीच उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है वे सभी योजनाएं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या फिर पूर्वाग्रह के चलते उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। बृजमोहन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के मकसद से अमृत मिशन योजना शहरों में चला रही है। इस मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार को हजारों करोड़ रुपए दिए जा चुके है। परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस योजना को पूर्ण करने में कोताही बरत रही है। उन्होंने कहा कि यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों से उनके पक्के घर का अधिकार छीन रही है। यहां तक कि पट्टा भी नहीं दिया जा रहा है।

इस अभियान में बृजमोहन अग्रवाल के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष तिवारी, रमेश सिंह ठाकुर, संनिमोर कार्यकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंठी, मलय महापंथ के रामकुमार धीवर, पार्षद मनोज वर्मा, गुलूचन्द्र दुबे, श्याम सुंदर अग्रवाल,संजू नारायण सिंह ठाकुर, सचिन मेघानी, चूड़ामणि निर्मलकर, मन्नू नायक, सुमित शर्मा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष मनीषा चंद्राकर, विशाल भूरा, हरिसिंग रूपाली शर्मा, पायल अंबवानी, चांदनी वलेरा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे।

बृजमोहन अग्रवाल ने वीरभद्र नगर में 20 लाख की लागत से बनने वाले जिम, सात लाख की लागत से बनने वाले पसिया समाज भवन तथा पांच लाख की लागत से बनने वाले सुत सारथी भवन का भूमि पूजन किया तथा यादव समाज भवन, गाड़ा समाज भवन, तथा दुलारी नगर भवन के लिए 5-5 लाख प्रदान करने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

अब बघेल का सिर्फ इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं: देवलाल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदरखाने चल रही सियासी उठापटक और कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी कु. शैलजा द्वारा हाल ही में लीं गई आकस्मिक गोपनीय बैठक का हवाला देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए के घोटालों और भ्रष्टाचार के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व क्या अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किनारा कर रहा है? देवलाल ठाकुर ने कहा कि ईडी की कार्रवाइयों के बाद गिरफ्तार लोगों की जमानत तक नहीं हो रही है और प्रदेश सरकार व कांग्रेस के लोग व्यर्थ ही बगलें झांक रहे हैं कि ईडी के पास घोटाले-भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा कि गिरफ्तार अधिकारियों व दलालों को जमानत तक के लाले पड़ना इस बात का प्रमाण है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। अन्यथा, क्या वजह है कि पवन खेड़ा के मामले में दो घंटों में जमानत कराने वाले अब तक घोटालों में गिरफ्तार लोगों की जमानत तक नहीं करा पाए? इस मामले में मुख्यमंत्री की उप सचिव तक हिरासत में है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस के मामले एकदम साफ प्रतीत हो रहे हैं कि या तो उनके विरुध्द मामले काफी मजबूत हैं या भूपेश यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने गिरफ्तार आरोपियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है।

2023 में प्रचंड बहुमत से फिर बनेगी सरकार : मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भरोसे का सम्मेलन और संभागीय सम्मेलनों के बाद विधानसभा स्तर पर होने वाले सम्मेलनों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रशिक्षण देकर जनता के बीच भेजेगी। हमारी तैयारी बूथों तक पूरी हो चुकी है। हमारे संगठन की मजबूती और सरकार के जनकल्याण कार्यों का मुकाबला करने में विपक्ष पूरी तरह नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनायें कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा हताहताई और कात्यनिक मुद्दों पर प्रदेश में राजनीति करना चाह रही जिसके कारण वह जनता से और दूर होते जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ते गया, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में हताशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है।

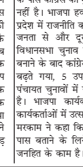

छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ: चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मोदी के जीवनी पर आधारित मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चंदेल ने भोपाल बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सीजी की भूपेश बघेल की सरकार हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित हुई है। वहां दो हजार (2000) करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैंहै ये अपने प्रेस को नोट में जारी किया है। यह शराब घोटाला बहुत सुनियोजित हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे देशभर में हो रही है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ मगर कोरोना काल में सरकार ने घर-घर में दारू पहुंचाई, एपा एक रैकेट काम कर रहा है।चंदेल का आरोप है कि नकली होलोग्राम बना कर, शराब सरकार चलाती है। हर दुकान पर 2 पेटी रखी जाती है। एक सरुवाश्र के खजाने में जाता था और एक भूपेश बघेल के किसी व्यक्ति के यहां जाता था। यह भ्रष्ट सरकार है। जनता के बीच में इसकी मान्यता नहीं है।

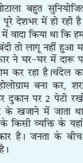

रोजगार पर झूठ बोलने में गोयबल्स को भी पीछे छोड़ भूपेश सरकार ने : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने एमबीबीएस डॉक्टरों तक के द्वारा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के सामने आए मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो स्थिति आज है, उसकी कोई और मिसाल देश में देखने को नहीं मिल सकती। बेरोजगारी को लेकर इतने झूठ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बोले हैं कि उसके सामने गोएबल्स भी शरमा जाए। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शत-प्रतिशत रोजगार का दावा करने वाली प्रदेश सरकार को इस बात पर शर्म से गड़ जाना चाहिए कि एक डॉक्टर भी छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने विवश हैं। छत्तीसगढ़ में इतने शर्मनाक हालात इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की क्या हालत कर दी है। श्री शर्मा ने कहा कि एक तरफ इलाज के अभाव में हजारों बच्चे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर तक को यह प्रदेश सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। यह स्थिति तब है, जब प्रदेश के अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कदम-कदम पर बेरोजगारों के साथ छल कर रही है। हाल ही लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित चयन सूची से यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार, उसकी प्रशासनिक मशीनरी और लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों से खुली धोखाधड़ी की है।

मोदी सरकार फैल तभी डॉक्टर, इंजीनियर भी मांग रहे है बेरोजगारी भत्ता: धनंजय

रायपुर। बेरोजगारी भत्ता के लिये डॉक्टर, इंजीनियर के आवेदन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर की बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना यह बताता है कि मोदी सरकार की बीस इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना कागजी घोड़ा निकला। ये योजना दूर के ढोल सुहावने की तरह है विज्ञापनों और मोदी के भाषणों के अलावा यह योजना कहीं दिखती नहीं है। अगर इन योजनाओं का वास्तविक में लाभ युवाओं को मिलता तो डॉक्टर बीई, एमटेक इंजीनियर एवं अन्य विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता बल्कि ये युवा खुद सक्षम बनते और अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सहयोग करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार दो करोड़ रोजगार देने में नकारा साबित हुई है। बेरोजगारी के मामले में देश 9 साल में 45 साल पुराने हालात में खड़ी हुई है। केंद्र की सरकारी विभाग में 30 लाख से अधिक पद रिक्त हैं और मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में 6 हजार 896 लोगों को मिला रोजगार

■ खाद्य प्रसंस्करण मिशन: साढ़े चार साल में 737 इकाईयों में 1398 करोड़ रूपए का हुआ निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप राज्य में पिछले साढ़े चार सालों में 737 नई इकाईयां स्थापित हुई है। इन इकाईयों में 1397 करोड़ 24 लाख रूपए का पूंजी निवेश हुआ है और 6 हजार 896 लोगों को रोजगार मिला है।

मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी विविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रूपए) तक अनुदान, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रूपए) तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रूपए की राशि तक का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के संरक्षण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (2.50 करोड़ रूपए अधिकतम) तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रूपए) तक का अनुदान अग्रवियों को प्रदाय किया जा रहा है।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुदान शर्तों में आवेदक की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए यानी आवेदक का नेटवर्थ आवेदन किये गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावों का बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिए, सावधि ऋण परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

बैंक व वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना पत्रक शामिल किये जाने चाहिए, जिनके लिए अनुदान मांगा गया है। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए निर्धारित पटकों में से किन्ही 2 परियोजना पटकों को स्थापना करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रदेश में एक नई योजना 'छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन' लागू है। खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापित करना, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना, उत्पादों को उन्नत करने उनकी क्षमता को बढ़ाने, कृषि उत्पादों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के मानकों में सुधार करना और संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना

खनिज व सहायक भौमिक अफसर की नियुक्ति का रास्ता साफ

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनिज अधिकारी और सहायक भौमिक अधिकारी के पद पर भर्ती से रहे हटा दिया है। स्थगन हटाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए उप महाधिवता संदीप दुबे ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने स्थगन देते हुए निर्देशित किया है। सभी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अधिन रहेगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेशित किया कि पटों पर

नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी कर दी जाए।

राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से खनिज अधिकारी और 11 सहायक भौमिक अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह पद 58 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से भरे जाने थे। इसकी अंतिम चयन सूची वेटिंग लिस्ट सहित 24 अगस्त को पीसस्री द्वारा जारी की गई और राज्य सरकार को प्रेषित की गई। इस बीच हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 2011 के आरक्षण संशोधन को निरस्त कर दिया, जिससे पुनः 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी सूची को निरस्त कर 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर नियुक्ति जारी करने की मांग की गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.